[2013] 7 एस. सी. आर. 519

लोकेश कुमार जैन

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 888/2013)

09 जुलाई, 2013

[टी. एस. ठाकुर और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय,न्यायाधीशगण]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस 482– एफ. आई. आर.–नौ साल से अधिक समय से लंबित जांच–को रद्द प्राथमिकीना–समान आरोपों पर विभागीय जांच में, अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट में दोषमुक्त प्राथमिकी दिया गया–आयोजित:तत्काल मामला एक उपयुक्त मामला है, जहां उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था–जांच एजेंसी को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं–जांच को लंबित रखना व्यर्थ होगा क्योंकि विभाग को यकीन नहीं है कि आरोप घर लाने के लिए जांच के लिए मूल रिकॉर्ड प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं–इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी द्वारा देरी की गई है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित जांच और मुकदमे की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया गया है और चूंकि अपीलकर्ता को पहले ही समान आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए प्राथमिकी रद्द कर दी गई है–भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 21–त्वरित जांच/परीक्षण।

महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, रुपये 4,39,617,का गबन देखा गया। जिला साक्षरता शिक्षा अधिकारी ने, 4–1–2000 पर, अपीलकर्ता के खिलाफ

एक प्राथमिकी आर. दर्ज की, जिसे उक्त कार्यालय में संबंधित अवधि के दौरान एल. डी. सी. कम–कैशियर के रूप में तैनात किया गया था। पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 2–6–2000 पर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन्होंने शिकायतकर्ता के आवेदन पर मामले को पुलिस को वापस भेज दिया। धारा 156(3) सीआर पी सी 18–11–2000 पर चूंकि जाँच में कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए अपीलकर्ता ने 6 साल से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद 482 सीआर पी सी उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस बीच, 15.12.2008 पर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में, अपीलकर्ता को विभागीय जांच में दोषमुक्त कर दिया गया था।

तत्काल अपील में, अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि वर्ष 2000 में समापन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, कोई प्रभावी जांच नहीं हो सकी और अपीलकर्ता 13 वर्षों से अधिक समय से उत्पीड़न का सामना कर रहा था; और जांच जारी रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि अपीलकर्ता को उन्हीं आरोपों पर विभागीय जांच रिपोर्ट में दोषमुक्त कर दिया गया था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

1.1 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है। त्वरित जांच और मुकदमे की आवश्यकता, क्योंकि दोनों दं.प्र.सं. के प्रावधानों के द्वारा अनिवार्य हैं, इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में जोर दिया गया है। [पैरा 13 और 15] [526–सी–डी; 528–8]

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1990 (3) पूरक। एससीआर 259 = 1992 (पूरक) 1 एस. सी. सी. 335; वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य, 2009 (1) एस. सी. आर. 517 = (2009) 3 एस. सी. सी. 355; हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, 1979 (3) एस. सी. आर. 169 = (1980) 1 एस. सी.

सी. 81; अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक, 1991 (3) पूरक। एस. सी. आर. 325 (1992) 1 एस. सी. सी. 225; पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 578–निर्दिष्ट।

1.2 तत्काल मामला एक उपयुक्त मामला है जिसमें उच्च न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था। 482 दं.प्र.सं.. यह विवादित नहीं है कि विभागीय कार्यवाही में जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांकित 15.12.2008 जाँच रिपोर्ट में, अपीलकर्ता को उन्हीं आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था जिनके लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, जांच के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद, आरोप के संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए। शिक्षा विभाग की फाइल से अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। सी. जे. एम. ने धारा 156(3) दं.प्र.सं. को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन पर अपने दिनांक 18–11–2000 के आदेश द्वारा एस. एच. ओ. को शिकायतकर्ता की सहायता से मामले की फिर से जांच करने और मूल रिकॉर्ड प्राप्त करने का निर्देश दिया। लेकिन नौ साल तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। [पैरा 27 और 32) [540–डी–ई; 545–ई–एच; 546–ए]

पी. एस. राज्य बनाम बिहार राज्य, 1996 (2) पूरक। एस. सी. आर. 631 = (1996) 9 सेक 1–संदर्भित।

1.3 रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, यहां तक कि इस अदालत के समक्ष दायर जवाबी शपथ पत्र के माध्यम से यह दिखाने के लिए कि रिकॉर्ड का पता लगाया गया है ताकि इसे जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सके। जवाबी शपथ पत्र में उल्लिखित मूल दस्तावेजों या साक्ष्य का पता लगाने की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से देरी का आरोप लगाया गया है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि उसने जांच के मामले में देरी की है। दूसरी ओर, जांच एजेंसी के समक्ष मूल रिकॉर्ड या अन्य साक्ष्य की उपलब्धता के बारे में प्रतिवादी की ओर से मौन रहने से पता

चलता है कि विभाग की ओर से निष्क्रियता के कारण देरी हुई थी। [पैरा 33] [446–बी–डी]

1.4 इसलिए, जांच को लंबित रखना व्यर्थ होगा क्योंकि राज्य साक्षरता कार्यक्रम निदेशालय सहित प्रतिवादी को यकीन नहीं है कि आरोप को घर लाने के लिए जांच के लिए मूल रिकॉर्ड कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विलंब प्रत्यर्थी के कारण होता है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित जांच और मुकदमे की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया गया है और चूंकि अपीलकर्ता को पहले ही समान आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को जांच के लिए लंबित रखना अनुचित है। इसलिए एफ. आई. आर. को रद्द प्राथमिकी दिया जाता है। [पैरा 33] [446–डी–एफ]

मामला कानून संदर्भः

1990 (3) एस. सी. आर. 259 पूरक पैरा 14 में निर्दिष्ट

1979 (3) एस. सी. आर. 169 पैरा 16 में निर्दिष्ट

1991 (3) पूरक एस. सी. आर. 325 पैरा 17 में निर्दिष्ट

(2002) (4) धारा 578 पैरा 18 को निर्दिष्ट

2009 (1) एस. सी. आर. 517 पैरा 19 में निर्दिष्ट

1996 (2) पूरक एस. सी. आर. 631 पैरा 28 में निर्दिष्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः दाण्डिक अपीलीय सं 888/2013

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एस. बी. आपराधिक विविध मामले 2006 की याचिका सं. 605 में 02.03.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से डॉ. सुमंत भारद्वाज, मृदुला रे भारद्वाज।

सोनिया माथुर, सुशी!कुमार दुबे, प्रगति नीखरा।उत्तरदाता के लिए

न्यायालय का निर्णय सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई। यह अपील अपीलकर्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा 2006 की एस. बी. आपराधिक विविध याचिका सं. 605 शीर्षक लोकेश कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य में पारित 2 मार्च, 2012 के आदेश के खिलाफ की गई है। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेशन, दौसा में अपीलकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की खंड 409 के तहत दर्ज भा.दं.सं. को रद्द करने से इनकार कर दिया। खंड 482 दं.प्र.सं. के तहत याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ किया गया थाः

> "यह आपराधिक गलती है। 8 खंड 482 दं.प्र.सं. के तहत याचिका दायर की गई है। दौसा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ. आई. आर. सं.1012000 को रद्द प्राथमिकीना। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से पूछा है कि क्या चा/इयान दायर किया गया है या नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि अभी भी चा/इयान दर्ज नहीं किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, आई. 0. के फैसले के आधार पर अभ्यावेदन/दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति है। याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार दायर किए गए निर्णय/दस्तावेजों/अभ्यावेदन के आधार पर मामले की जांच करनी चाहिए और उसके बाद संबंधित अदालत के समक्ष प्रगति दर्ज करनी चाहिए। तदनुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है।"

2. दलों के प्रतिद्वंद्वी रुख की सराहना आदेशने के लिए, पृष्ठभूमि के तथ्यों पर अधिक विस्तार से ध्यान देना आवश्यक होगा।

3. अपीलकर्ता को जिला साक्षरता शिक्षा अधिकारी, दौसा के कार्यालय में नवंबर, 1996 से नवंबर, 1997 की अवधि के दौरान लोअर डिवीजन क्लर्क (संक्षेप में, 'एल. डी. सी.') के रूप में तैनात किया गया था। 4 जनवरी, 2000 को जिला साक्षरता शिक्षा अधिकारी, दौसा ने पुलिस स्टेशन, दौसा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफ. आई. आर.') दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जब अपीलकर्ता को एल. डी. सी.–सह–कैशियर के रूप में तैनात किया गया था, तो उसके द्वारा एक वित्तीय अनियमितता की गई थी। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, रुपये के गबन का पता चला है। बिलों और दस्तावेजों की मूल प्रतियां महालेखा परीक्षक के कार्यालय और राज्य साक्षरता कार्यक्रम के लिए निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध थीं। इसलिए महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने वर्ष 1996–1997 में कथित रूप से हुई घटना की प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें अपीलकर्ता को एक आरोपी के रूप में शामिल किया गया। जाँच के बाद, पुलिस ने 2 जून, 2000 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा (इसके बाद "सीजेएम, दौसा" के रूप में संदर्भित) के समक्ष मामले में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

5. सीजेएम, दौसा के समक्ष मामले विचाराधीनता रहने के दौरान, शिकायतकर्ता ने 18 नवंबर, 2000 को सीजेएम, दौसा के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें मामले को आगे की जांच के लिए पुलिस को वापस भेजने का अनुरोध किया गया। सीजेएम, दौसा ने 18 नवंबर, 2000 के आदेश के माध्यम से दं.प्र.सं. की खंड 156 (3) के तहत मामले को पुलिस को वापस भेज दिया। तब से मामला पुलिस के पास लंबित था। अपीलकर्ता के अनुसार, उन्होंने कई बार पुलिस अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की और उनका प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अभी भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न तो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही चालान दायर किया जा रहा है और तब से मामला लंबित है। इससे पहले

अंतिम रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस ने सूचित किया कि बिलों की मूल प्रतियां और अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कोई जांच नहीं की जा सकी।

6. छह साल से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद, अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष खंड 482 दं.प्र.सं. के तहत आपराधिक विविध याचिका सं.605/2006 के तहत एक याचिका दायर की, ताकि पुलिस स्टेशन, दौसा में पंजीकृत एफ. एल. आर. सं.10/2000 को खारिज किया जा सके।

7. इस बीच, अपीलकर्ता के खिलाफ उन्हीं आरोपों के लिए एक विभागीय जांच शुरू की गई थी जिसमें जांच अधिकारी ने पूछताछ के बाद 15 दिसंबर, 2008 को अपीलकर्ता को आरोपों से बरी करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

8. उच्च न्यायालय ने 2 मार्च, 2012 के विवादित आदेश द्वारा प्राथमिकी में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया और फिर से मामले को अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित आधारों पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दीः

(क) सी. जे. एम., दौसा द्वारा पारित आदेश की तारीख से अपीलकर्ता 13 वर्षों से अधिक समय से जांच के उत्पीड़न का सामना कर रहा है जो दस्तावेजों की आपूर्ति की कमी के कारण आज तक पूरा नहीं हुआ है।

(ख) बहुत पहले वर्ष 2000 में समापन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद कोई प्रभावी जांच नहीं हुई है।

(ग) यदि दस्तावेज़ की अनुपस्थिति में में भी जाँच जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह व्यर्थ होगा और केवल अपीलकर्ता को परेशान प्राथमिकी सकता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2009 में अपीलकर्ता के खिलाफ किए गए उक्त

आरोपों के लिए विभागीय जाँच में भी अपीलकर्ता को दोषमुक्त प्राथमिकी दिया गया था क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ वर्तमान एफ़. आई. आर. का आधार बनने वाले किसी भी आरोप को साबित नहीं किया जा सका था।

10. उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा किया, जिन पर इस फैसले के निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की जाएगी।

11. राजस्थान राज्य ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया है। उनके अनुसार, जाँच अभी भी जारी है और अपीलकर्ता स्वयं अपने द्वारा अपनाए गए असहयोगी रवैये के कारण इसमें देरी कर रहा है। किसी भी मामले में; अब तक की गई जांच से, अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 409 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से सामने आया है और केवल इसी आधार पर, एफ. आई. आर. को रद्द प्राथमिकीने की याचिका खारिज की जा सकती है और कानूनी प्रक्रिया को तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए।

12. यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाबी शपथ पत्र में उपरोक्त रुख अपनाया गया है, प्रत्यर्थी दस्तावेजों के बारे में चुप है अर्थात क्या उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कोई विशिष्ट उदाहरण यह सुझाव देने के लिए नहीं दिखाया गया कि अपीलकर्ता किसी विशेष तिथि पर जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने में विफल रहा।

13. इस प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले कि क्या दी गई परिस्थितियों में उच्च न्यायाधीशालय को किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के दं.प्र.सं. 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, इस न्यायाधीशालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान देना वांछनीय होगा जो उन मामलों की श्रेणियों से संबंधित हैं जिनमें खंड 482 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायाधीशालय द्वारा न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है।

14. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 (पूरक) 1 धारा 335 में इस न्यायालय ने दृष्टांत के माध्यम से मामलों की श्रेणियों को तैयार करते हुए कहा, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए वनाच्छादित प्रावधानों के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और निम्नानुसार टिप्पणी की:–

> "102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की खंड 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायाधीशालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया में दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
>
> (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में किए गए ए/लीगेशन, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।
>
> (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो संहिता की खंड 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा

संहिता की खंड 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराती है। (3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में किए गए अनियंत्रित कानून और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं प्राथमिकीते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं। (4) जहां, एफ. आई. आर. में ए/लिगेशंस एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं प्राथमिकीते हैं, लेकिन केवल एक गैर–संज्ञेय अपराध का गठन प्राथमिकीते हैं, वहां एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की खंड 155 (2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में दिए गए कथन इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्प्राथमिक्षीष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही प्राथमिकीने के लिए पर्याप्त आधार है। (6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था को और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, वहां एक स्पष्ट कानूनी बाधा है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

15. शीघ्र जाँच की आवश्यकता है। और मुकदमे के रूप में दोनों दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अक्षर और भावना द्वारा अनिवार्य हैं, इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में जोर दिया गया है।

16. हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, (1980) 1 एस. सी. सी. 81 में इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है; कि ऐसी प्रक्रिया किसी प्रक्रिया की झलक नहीं है, बल्कि प्रक्रिया "उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत" होनी चाहिए; और इससे, निस्संदेह, त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रवाहित होता है। इस न्यायालय ने आगे कहा किः

> "8. जमानत पर मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदी को रिहा करने या उसकी उपस्थिति के लिए बिना किसी प्रतिभूति के व्यक्तिगत मुचलके के निष्पादन पर न्यायिक शक्ति के प्रयोग के संबंध में, मुझे यह संक्षेप में कहना है। दंड प्रक्रिया संहिता के मौजूदा प्रावधानों के भीतर इस संबंध में शक्ति का विस्तार है, और यह अदालतों पर है कि वे इसका प्रयोग करने में अपने विवेकाधिकार की प्रकृति और सीमा से पूरी तरह से परिचित हों। मुझे लगता है कि अब शक्ति के यांत्रिक अभ्यास को स्वीकार करना संभव नहीं है। प्रतिभूति की कितनी राशि की आवश्यकता होनी चाहिए या बांड में मौद्रिक दायित्व की मांग एक ऐसा मामला है जिसमें कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पूरा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन व्यक्ति भाग न जाए या मुकदमे से खुद को न छिपाए, उस प्रश्न के निर्धारण में प्रवेश करने वाले सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 1966 के संयुक्त राज्य जमानत सुधार

अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान से इस बात की संक्षिप्त धारणा ली जा सकती है कि क्या विचार किए जा सकते हैं:

"यह निर्धारित करने में कि रिहाई की कौन सी शर्तें उचित रूप से उपस्थिति का आश्वासन देंगी, न्यायिक अधिकारी, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आरोपित अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों, अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य का वजन, अभियुक्त के पारिवारिक संबंधों, रोजगार, वित्तीय संसाधनों, चरित्र और मानसिक स्थिति, समुदाय में उसके निवास की अवधि, दोषसिद्धि का उसका रिकॉर्ड, और अभियोजन या अदालत की कार्यवाही में उपस्थित होने या भागने से बचने के लिए अदालत की कार्यवाही में या भागने के उसके रिकॉर्ड को ध्यान में रखेगा।

ये ऐसे विचार हैं जिन्हें प्रतिभूति या मौद्रिक दायित्व की राशि निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। शायद, यदि ऐसा किया जाता है तो भारत में पूर्व–परीक्षण रिहाई की प्रचलित प्रणाली पर परिचारक के दुर्व्यवहार से बचा जा सकता है या किसी भी घटना में, बहुत कम किया जा सकता है।"

17. अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1992) 1 धारा 225 में, न्यायालय ने सावधानी के साथ 11 प्रस्ताव तैयार किए कि इन्हें संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए और ये केवल दिशाध्यान देने के रूप में काम करने के लिए थे।

86. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं, जो दिशानिर्देशों के रूप में काम करते हैं। हमें पहले से सचेत रहना चाहिए कि ये प्रस्ताव संपूर्ण नहीं हैं। सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। न ही कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित करना संभव है। ये प्रस्ताव इस प्रकार है:

(1) संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया अभियुक्त पर तेजी से मुकदमा चलाने का अधिकार देती है। त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का अधिकार है। यह तथ्य कि त्वरित मुकदमा भी जनहित में है या यह सामाजिक हित की भी सेवा करता है, इसे अभियुक्त के अधिकार से कम नहीं बनाता है। यह सभी संबंधित लोगों के हित में है कि परिस्थितियों में अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का जल्द से जल्द निर्धारण किया जाए।

(2) अनुच्छेद 21 से आने वाले त्वरित सुनवाई के अधिकार में सभी चरण शामिल हैं, अर्थात् जांच, जांच, परीक्षण, अपील, संशोधन और पुनः सुनवाई का चरण। इस तरह, इस न्यायालय ने इस अधिकार को समझ लिया है और प्रतिबंधित दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।

(3) अभियुक्त के दृष्टिकोण से त्वरित सुनवाई के अधिकार में अंतर्निहित चिंताएँ है:

(क) रिमांड और पूर्व–दोषसिद्धि निरोध की अवधि यथासंभव कम होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त को उसकी दोषसिद्धि से पहले अनावश्यक या अनावश्यक रूप से लंबे कारावास के अधीन नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) अनावश्यक रूप से लंबी जांच, जांच या मुकदमे के परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय और शांति के लिए चिंता, चिंता, खर्च और अशांति न्यूनतम होनी चाहिए; और

(ग) अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरूप अभियुक्त की अपना बचाव करने की योग्यता में हानि हो सकती है, चाहे वह मृत्यु, गुमशुदगी या गवाहों की अनुपलब्धता के कारण हो या अन्यथा।

(4) साथ ही, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आमतौर पर आरोपी ही कार्यवाही में देरी करने में रुचि रखता है। जैसा कि अक्सर बताया जाता है, "देरी एक ज्ञात रक्षा रणनीति है"। चूँकि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, इसलिए देरी आमतौर पर अभियोजन पक्ष को पूर्वाग्रहित

करती है। गवाहों की अनुपलब्धता, समय के साथ साक्ष्य का गायब होना वास्तव में अभियोजन पक्ष के हितों के खिलाफ काम करता है। बेशक, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अभियोजन पक्ष, किसी भी कारण से, कार्यवाही में देरी करता है। इसलिए, हर मामले में, जहां त्वरित सुनवाई के अधिकार का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, पहला सवाल रखा जाना चाहिए और जवाब दिया जाना चाहिए–देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? अपने अधिकारों और हितों को सही साबित करने के लिए सद्भावना से किसी भी पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही, जैसा कि वे समझते हैं, को देरी की रणनीति के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने में लगने वाले समय को देरी के रूप में गिना जा सकता है। यह बिना कहे चला जाता है कि केवल गणना के दिन में देरी करने के लिए की गई तुच्छ कार्यवाही या कार्यवाही को सद्भावना से की गई कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है। केवल यह तथ्य कि एक आवेदन/याचिका स्वीकार की जाती है और एक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन का आदेश अपने आप में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कार्यवाही तुच्छ नहीं है। बहुत बार ये अवशेष एकपक्षीय प्रतिनिधित्व पर प्राप्त किए जाते हैं।

(5) यह निर्धारित करते समय कि क्या अनुचित देरी हुई है (जिसके परिणामस्वरूप त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है) अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों और गवाहों की संख्या, संबंधित न्यायालय के कार्यभार, प्रचलित स्थानीय स्थितियों आदि सहित सभी परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए–जिसे प्रणालीगत देरी कहा जाता है। यह सच है कि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है और राज्य में न्यायपालिका भी शामिल है, लेकिन ऐसे मामलों में पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण के बजाय यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

(6) प्रत्येक विलम्ब आवश्यक रूप से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता है। कुछ देरी वास्तव में उसके लाभ के लिए काम कर सकती है। जैसा कि पॉवेल, जे. ने बार्कर में देखा है।

"यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ऐसी प्रणाली में देरी कितनी लंबी है जहां न्यायाधीश त्वरित लेकिन जानबूझकर माना जाता है। यही विचार व्हाइट, जे. द्वारा यू. एस. बनाम में कहा गया है। निम्नलिखित शब्दों में कहें:

> ".....त्वरित विचारण का छठा संशोधन अधिकार अनिवार्य रूप से सापेक्ष है, विलंब के साथ सुसंगत है, और इसके आवश्यक अवयवों के रूप में केवल गति के बजाय व्यवस्थित अभियान है; और क्या अभियोजन को पूरा करने में देरी अधिकारों के असंवैधानिक अभाव के बराबर है, यह सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
>
> हालाँकि, अत्यधिक जोंग देरी को पूर्वाग्रह के अनुमानित प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। इस संदर्भ में, अभियुक्तों को कैद करने का तथ्य भी एक प्रासंगिक तथ्य होगा। अभियोजन पक्ष को उत्पीड़न नहीं बनने दिया जाना चाहिए। लेकिन अभियोजन कब उत्पीड़न बन जाता है, यह फिर से किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।"

(7) हम 'मांग' नियम को न तो पहचान सकते हैं और न ही उसे लागू कर सकते हैं। एक अभियुक्त स्वयं पर मुकदमा नहीं चला सकता है; अभियोजन पक्ष के कहने पर अदालत द्वारा उसका मुकदमा चलाया जाता है। इसलिए, त्वरित सुनवाई से इनकार करने की अभियुक्त की याचिका को यह कहकर पराजित नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त ने किसी भी समय त्वरित सुनवाई की मांग नहीं की थी। यदि किसी मामले में, उसने ऐसी मांग की थी और फिर भी उस पर तेजी से मुकदमा नहीं चलाया गया, तो यह उसके पक्ष में एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन आरोपी के खिलाफ त्वरित सुनवाई के लिए केवल गैर–पूछताछ नहीं की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मांग नियम की प्रासंगिकता काफी हद तक कम हो गई है। बार्कर और अन्य सफल मामलों में।

(8) अंततः, अदालत को कई प्रासंगिक कारकों–'संतुलन परीक्षण' या 'संतुलन प्रक्रिया'–को संतुलित और तौलना होता है और प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना होता है कि क्या किसी मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया है।

(9) सामान्य तौर पर, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी आरोपी के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो आरोप या दोषसिद्धि, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यह एकमात्र खुला पाठ्यक्रम नहीं है। किसी मामले में अपराध की प्रकृति और अन्य परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि कार्यवाही को रद्द करना न्यायाधीश के हित में न हो। ऐसे मामले में, अदालत के लिए ऐसा अन्य उचित आदेश देने का अधिकार है–जिसमें एक निश्चित समय के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का आदेश शामिल है जहां मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है या सजा को कम करना जहां मुकदमा समाप्त हुआ है–जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और न्यायसंगत माना जा सकता है।

(10) अपराधों के मुकदमे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना न तो उचित है और न ही व्यावहारिक है। ऐसा कोई भी नियम योग्य होने के लिए बाध्य है। इस तरह के नियम को केवल अभियोजन पक्ष के कंधों पर औचित्य साबित करने का बोझ डालने के लिए विकसित नहीं किया जा सकता है। त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार करने की शिकायत के प्रत्येक मामले में, यह मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष पर है कि वह देरी को उचित ठहराए और उसकी व्याख्या करे। साथ ही, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह शिकायत पर फैसला सुनाने से पहले किसी दिए गए मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी छठे संशोधन के बावजूद बार–बार ऐसी कोई बाहरी समय–सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। न ही हम यह समझते हैं कि ऐसी कोई बाहरी सीमा तय नहीं करने से त्वरित सुनवाई के अधिकार की गारंटी अप्रभावी हो जाती है।

(11) त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार और उस कारण से राहत के आधार पर आपत्ति को पहले उच्च न्यायालय को संबोधित किया जाना चाहिए। भले ही उच्च न्यायालय ऐसी याचिका पर विचार करता है, आम तौर पर उसे गंभीर और असाधारण प्रकृति के मामले को छोड़कर कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय में ऐसी कार्यवाही का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

18. पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 578 में इस न्यायालय के सात विद्वान न्यायाधीशों ने सामान्य कारण मामले (I) में निर्धारित अनुपात की वैधता पर विचार किया जैसा कि सामान्य कारण मामले (I) में संशोधित किया गया है (II) और (II) मामले जिनमें इस न्यायालय ने सीमा की अवधि निर्धारित की है जिसके बाद किसी आपराधिक मामले या आपराधिक कार्यवाही का मुकदमा जारी नहीं रह सकता है और ऐसे मामलों में आरोपी को बरी या आरोपमुक्त करने के आदेश द्वारा कार्यवाही को बंद करने का निर्देश दिया। पी. रामचंद्र राव (उपर्युक्त) के उक्त मामले में इस विषय पर प्राधिकरण के विस्तृत विचार के बाद इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "29. सभी पूर्वगामी कारणों से, हमारी राय है कि सामान्य कारण मामले (I) [सामान्य कारण (II) में संशोधित] और राज देव शर्मा (I) और (II) में न्यायालय की सीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो सकती थी, जिसके बाद किसी आपराधिक मामले या आपराधिक कार्यवाही का मुकदमा जारी नहीं रह सकता है और आरोपी को बरी करने या आरोपमुक्त करने के आदेश के बाद अनिवार्य रूप से बंद किया जाना चाहिए। निष्कर्ष में हम मानते हैं:
>
> (1) ए. आर. अंतुले मामले में उक्ति सही है और अभी भी मैदान में है।

(2) संविधान के अनुच्छेद 21 से उभरने वाले प्रस्ताव और ए. आर. अंतुले मामले में दिशानिर्देशों के रूप में निर्धारित त्वरित सुनवाई के अधिकार की व्याख्या त्वरित सुनवाई के अधिकार का पर्याप्त रूप से ध्यान रखती है। हम उक्त प्रस्तावों का समर्थन और पुष्टि करते हैं।

(3) ए. आर. अंतुले मामले में निर्धारित दिशा–निर्देश संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि केवल उदाहरणात्मक हैं। उनका उद्देश्य कठोर और तेज़ नियमों के रूप में काम करना या स्ट्रैटजैकेट सूत्र की तरह लागू करना नहीं है। उनकी प्रयोज्यता प्रत्येक मामले की तथ्य स्थिति पर निर्भर करेगी। सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है और कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है।

(4) सभी आपराधिक कार्यवाहियों के समापन के लिए कोई बाहरी सीमा निर्धारित करना या निर्धारित करना न तो उचित है, न ही व्यवहार्य है, न ही न्यायिक रूप से अनुमत है। कॉमन कॉज (I), राज देव शर्मा (I) और राज देव शर्मा (II) में बनाए गए कई निर्देशों में निर्धारित समय–सीमा या सीमा के बार इस तरह से निर्धारित या तैयार नहीं किए जा सकते थे और ये अच्छे कानून नहीं हैं। आपराधिक अदालतें यह कहने के लिए बाध्य नहीं हैं:सामान्य कारण मामला (I), राज देव शर्मा मामला (I) और (II) में दिए गए निर्देशों के अनुसार, केवल समय बीतने के कारण मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करें। उन निर्णयों में निर्धारित समय की अधिक से अधिक अवधि मुकदमे या कार्यवाही के कब्जे वाले न्यायालयों द्वारा अनुस्मारक के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकती है जब उन्हें उनके सामने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपने न्यायिक दिमाग को लागू करने के लिए राजी किया जा सकता है और ए. आर. अंतुले मामले में बताए गए कई प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है और यह तय किया जा सकता है कि क्या मुकदमे या कार्यवाही में इतनी अत्यधिक देरी हुई है कि इसे दमनकारी और अनुचित कहा जा सकता है। इस तरह की समय–सीमा को किसी भी अदालत द्वारा मुकदमे या कार्यवाही को आगे जारी रखने के

लिए एक बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही न्यायालय द्वारा इसे समाप्त करने और आरोपी को बरी करने या आरोपमुक्त करने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य करने के रूप में माना जाएगा।

(5) आपराधिक अदालतों को त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 309,311 और 258 के तहत अपनी उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। एक सतर्क और मेहनती विचारण न्यायाधीश किसी भी दिशानिर्देश की तुलना में इस तरह के अधिकार का बेहतर रक्षक साबित हो सकता है। उचित मामलों में, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को उचित राहत या उपयुक्त निर्देश प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है।

(6) यह भारत संघ और राज्य सरकारों को आवश्यक धन, श्रमशक्ति और बुनियादी ढांचा प्रदान करके न्यायपालिका को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से मजबूत करने के उनके संवैधानिक दायित्व की याद दिलाने का एक उपयुक्त अवसर है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि सरकारें कार्रवाई करेंगी।

19. वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य, (2009) 3 धारा 355 में इस न्यायालय ने विलंब के कारण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के प्रश्न पर विचार किया। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि त्वरित जांच और मुकदमा, दोनों दं.प्र.सं. में निहित हैं। त्वरित सुनवाई के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है और यह न केवल अदालत में वास्तविक कार्यवाही पर लागू होता है, बल्कि इसमें पूर्ववर्ती पुलिस जांच भी शामिल है।

20. वकील प्रसाद सिंह (उपरोक्त) में पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग (सतर्कता), मुज़फ़्फ़रपुर के कार्यालय द्वारा एक सिविल ठेकेदार द्वारा अभियुक्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (सिविल) मुज़फ़्फ़रपुर में एक सहायक अभियंता के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के आधार पर एक तलाशी अभियान चलाया गया था, जो कथित रूप से

उसके द्वारा निष्पादित सिविल कार्य के लिए भुगतान जारी करने के लिए अवैध संतुष्टि के रूप में Rs.1000 की राशि की मांग कर रहा था। यह मामला 8 अप्रैल, 1981 को शुरू किया गया था और उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ 28 फरवरी, 1982 को आरोप–पत्र दायर किया गया था। मजिस्ट्रेट ने 9 दिसंबर, 1982 को संज्ञान लिया लेकिन कुछ भी ठोस नहीं हुआ। अभियुक्त ने उक्त अपराधों का संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष खंड 482 दं.प्र.सं. के तहत एक याचिका दायर की, इस आधार पर कि पुलिस निरीक्षक, जिन्होंने जांच की थी, जिसके आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया था, उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। याचिका स्वीकार करना। उच्च न्यायालय ने 7 दिसंबर, 1990 के अपने आदेश द्वारा मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया और अभियोजन पक्ष को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। हालाँकि, आगे कोई प्रगति नहीं हुई और मामला 1998 तक वहीं रुका रहा, जब अभियुक्त ने खंड 482 दं.प्र.सं. के तहत एक और याचिका दायर की, जिससे इस न्यायालय के समक्ष अपील को जन्म मिला।

21. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (ऊपर), हुसैनारा खातून (ऊपर), अब्दुल रहमान अंतुले (ऊपर) आदि सहित कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात और वकील प्रसाद सिंह (ऊपर) मामले के प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार था कि यह एक उपयुक्त मामला था जहां उच्च न्यायालय को खंड 482 दं.प्र.सं. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था क्योंकि राज्य को इस बात का यकीन नहीं था कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं और यदि ऐसा है, तो क्या इसे दिया गया है या नहीं और मामला लगभग 17 साल से लंबित था और अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।

22. तथ्यात्मक परिदृश्य का पता लगाने के लिए, हमने पृष्ठभूमि को अधिक विस्तार से देखा है जैसा कि यहाँ नीचे उल्लेख किया गया हैः

23. 4 जनवरी, 2000 को शिकायतकर्ता–जिला साक्षरता और शिक्षा मिशन अधिकारी, दौसा द्वारा प्राथमिकी में निम्नलिखित आरोप लगाया गया था, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया हैः

> "प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्षरता और निरंतर शिक्षा मिशन का कार्यालय,
> दौसा फाइल सं.672 दिनांक 4.1.2000
>
> को,
>
> एसएचओ
>
> पुलिस स्टेशनःदौसा
>
> विषयःजैन एल. डी. सी. (कैशियर) द्वारा 11.96–11.97 अवधि के लिए लंबित बिल की राशि के दुरुपयोग के संबंध में,
>
> उपरोक्त विषय के संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि श्री. लोअर डिवीजन क्लर्क (कैशियर) लोकेश जैन, जो वर्तमान में कैशियर के पद पर काम करते हुए निलंबित हैं, ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, जिसके लिए वित्तीय विभाग और कैग के कार्यालय ने एक जांच की है जो इसके साथ संलग्न है। जांच रिपोर्ट के अनुसार 4,39,617 रुपये का गबन किया गया है, मूल बिल की सभी प्रतियां सीएजी के कार्यालय में मौजूद हैं और मूल दस्तावेज राज्य साक्षरता और शिक्षा मिशन निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध हैं।
>
> इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि कैग के कार्यालय के संलग्न जांच रिपोर्ट के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
>
> संलग्नक पूछताछ 8 पृष्ठ

एसडी/– जी

जिला साक्षरता और शिक्षा

मिशन अधिकारी, दौसा"

24. जाँच करने के बाद, जाँच एजेंसी

2 जून, 2000 को सी. जे. एम., दौसा के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"मामले के संक्षिप्त तथ्यः.

आदरणीय साहब,

वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि 4.1.2000 पर मुरारीलाल एस/ओ एस हरनुख प्रसाद, जातिः 56 वर्षीय ब्राह्मण, रियो गाँवः ऊंच, पी. एस., नंदबाई, जिलाः भरतपुर वर्तमान में जिला साक्षरता और मिशन शिक्षा अधिकारी, दौसा के रूप में तैनात है, जिसे पुलिस स्टेशन में पेश किया गया और श्री के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई। लोकेश कुमार जैन (एल. डी. सी.) वर्तमान में निलंबन के तहत है कि लोकेश जैन ने कैशियर के रूप में काम करते हुए कुछ वित्तीय अनियमितताएं कीं जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा की गई जांच के दौरान सामने आईं, जिसके अनुसार रुपये की हेराफेरी दिखाई दी है।

रिपोर्ट की प्रति संलग्न है; जी. ए. जी. के मूल दस्तावेज और राज्य साक्षरता और मिशन शिक्षा कार्यालय के मूल दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी आर. सं.1012000 यू/एस 409 ऑफ/पी. सी. दर्ज की गई और जाँच गवाहों को दर्ज किया गया। मामले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभाग से कई बार मौखिक अनुरोध किए गए थे, लेकिन

बाद में 13 पर यह अप्रभावी रहा। 4.2000.धारा 91 करोड़ के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए पी. सी. लेकिन इसके बावजूद कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। फिर से 21.4.2000 पर यू/एस 91 दं.प्र.सं. के तहत एक नोटिस जारी किया गया और निर्देश दिए गए कि दस्तावेज़ की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। कोई दस्तावेज़, कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था। श्री के स्टेटमेइ1ट्स से संबंधित जाँच के दौरान। कैलाश और राम किशोर बैरवा (जूनियर एकाउंटेंट) जिन्होंने कहा कि जांच के दौरान क्रेडिट डेबिट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था और उन्होंने आई. ओ. नं. टी. पी. 31162, इस संबंध में एक शिकायत दी गई थी, सी. ओ. ने विभाग को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए भी लिखा है, लेकिन उन्होंने इसे प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता दिखाई। वर्तमान मामले में, अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कई अनुरोध किए गए थे लेकिन उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया था। श्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। शिक्षा विभाग की फाइल से लोकेश जैन। मामला लंबे समय से लंबित है और निकट भविष्य में रिकॉर्ड की उपलब्धता की कोई संभावना नहीं है। संबंधित विभागों से अभिलेख प्राप्त होने पर आगे की जांच की जाएगी। इसलिए अपर्याप्त साक्ष्य के कारण एफ. आर. सं.6712000 को दयालु अवलोकन और स्वीकृति के लिए दायर किया जा रहा है।"

25. अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन पर, सीजेएम, दौसा ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष

जिलाःदौसा, दौसा

शिकायतकर्ताःमुरारी लाल

प्राथमिकी आर. सं. 1012000

18.11.2000

अति.लो.अभि. प्रस्तुत करें।

वर्तमान शिकायतकर्ताःश्री मुरारी लाल शर्मा

इस मामले में अंतिम रिपोर्ट इस दावे के साथ दायर की गई है कि मूल रिकॉर्ड एस. एच. ओ. को प्रदान नहीं किया गया है और इसलिए जांच नहीं की जा सकती है। शिकायतकर्ता मुरारी लाल उपस्थित है और वह उक्त अभिलेख प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।

इसलिए यू/एस 156 (3) दं.प्र.सं. एस. एच. ओ. दौसा को श्री की सहायता से मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया जाता है। मूल अभिलेख प्राप्त करने के लिए मुरारी लाल साक्षरता और मिशन शिक्षा अधिकारी। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाती है, केस डायरी वापस की जा रही है।

एसडी/– सीजेएम

जिलाःदौसा, दौसा"

26. इसके बाद, अभिलेख पर कुछ भी नहीं बताता है कि सीजेएम, दौसा द्वारा पारित 18 नवंबर, 2000 के आदेश के बाद प्रतिवादी ने आगे की जांच के लिए जांच एजेंसी के समक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत किए।

27. कम से कम नौ वर्षों से अधिक समय तक अधिकारियों द्वारा न तो मूल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सका और न ही अपीलकर्ता को फंसाने के लिए कोई प्रासंगिक दस्तावेज पाया जा सका, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 15 दिसंबर,

2008 की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिसमें अपीलकर्ता को उन्हीं आरोपों से बरी किया गया था जिनके लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी जांच अधिकारी द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद अपचारी अधिकारी श्री के अपराध को स्थापित करने के लिए बैंक से मूल सहित कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहा। लोकेश कुमार जैन। 15 दिसंबर, 2008 की जाँच रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग यहाँ उद्धृत किए गए है:

विभिन्न तिथियों के अंत के बाद अभियोजन अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

क) लेखा पुस्तक, एनकैशमेंट रजिस्टर और बिल रजिस्टर (सभी फोटोकॉपी)

ख) एस बी बी जे बैंक शाखा दौसा द्वारा जारी किया गया दिनांक 26–04–2004 का पत्र जो साक्षरता अधिकारी, दौसा के कार्यालय को संबोधित था।

ग) कोषागार के खजांची के कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 21–11–2008 का पत्र।

घ) मुख्य लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी सीए/II/दौसा/176 दिनांकित 04–11–2008 वाला पत्र।

उपरोक्त दस्तावेजों के अनुसार, मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी कथित अधिकारी को दिखाई गई थी। फोटोकॉपी के अवलोकन के बाद, कथित अधिकारी ने इससे इनकार करते हुए फिर से 12–01–2009 पर आवेदन दायर किया है और मांग की है कि उसे मूल रिकॉर्ड को पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। कथित अधिकारी द्वारा आपत्तियाँ उठाई गईं और अभियोजन अधिकारी को मूल रिकॉर्ड और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया। अगली कई तारीखों पर भी अभियोजन अधिकारी कोई अन्य मूल रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहा। 24–07–2009 पर, कथित अधिकारी ने सहायक के साथ अभियोजन पक्ष की उपस्थिति में मामले और संबंधित दस्तावेज और पत्रों का अध्ययन किया और लिखित तर्क प्रस्तुत करने के उद्देश्य से

मामले को 29–07–2009 के लिए तय किया गया था। सहायक के साथ उपस्थित बचाव पक्ष ने अपना लिखित तर्क दायर किया है जिसे रिकॉर्ड में लिया गया था। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार गवाह/साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का एक अंतिम और अंतिम अवसर दिया गया था। निर्धारित तिथि पर न तो अभियोजन पक्ष और न ही बचाव पक्ष ने अपना गवाह/साक्ष्य/दस्तावेज दाखिल किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, श्री जैन के खिलाफ 22–12–2007 पर निम्नलिखित अपराध का आरोप लगाया गया थाः

1. कि आप श्री लोकेश कुमार जैन (कैशियर) जिला शिक्षा और शिक्षा अधिकारी दौसा के कार्यालय में 20–11–1995 से 13–11–1997 तक हैं, आपको लेखाकार का काम दिया गया था।

11196 से 11197 की जांच रिपोर्ट के अनुसार, आपके द्वारा रुपये का गबन किया गया था।

आरोप का विवरण इस प्रकार दर्शाया गया हैः

क) एफ. वी. सी. के बिलों की राशि रु। 65, 3301 बिल रजिस्टर में दर्ज पाया जाता है, लेकिन कोषागार से बिल के पारित होने के बाद, जिसकी प्रविष्टि नकदीकरण रजिस्टर और लेखा पुस्तकों में नहीं पाई गई थी। कथित अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा दायर अभिलेखों (कैश बुक, एनकैशमेंट रजिस्टर) की फोटोकॉपी में उपरोक्त तरीके से एफ. वी. सी. के किसी भी बिल की कोई प्रविष्टि नहीं है। केवल अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बिल दर्ज किया गया है, जिसका पहले का प्रविष्टि रिकॉर्ड नियमों के अनुसार दर्ज किया गया है। दोनों एजेंसियों का पत्र बैंकों से एफ. वी. सी. के विभिन्न बिलों की निकासी के संबंध में और राजकोष से पारित होने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था और उक्त बिलों का उल्लेख बिल रजिस्टर (पी–2) (पी–3) में भी पाया गया है। बिल रजिस्टर के अलावा अन्य अभिलेखों में बिलों की प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों (पी–2) (पी–3) के आधार पर, मूल बिल

जो मुख्य लेखा परीक्षक के कार्यालय से प्राप्त किया जाना था, प्राप्त नहीं हुआ था (पी–4)।

इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति ने बैंक से उक्त बिलों को वापस लिया है और न ही मूल बिल रिकॉर्ड में है, जिन पृष्ठों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बैंक से उक्त बिलों की राशि किसने निकाली है। उक्त साक्ष्य (पी–2) (पी–3) अपराध के पहले भाग (1) के आलोक में, बैंकों से उक्त बिलों की राशि निकालकर राशि के गबन का अपराध अपचारी अधिकारी श्री लोकेश कुमार जैन के अपराध को स्थापित नहीं कर सका। अतः अभियुक्त के संबंध में अपराध का हिस्सा स्थापित नहीं किया गया है।

2. एफ. वी. सी. के बिलों की प्रविष्टि रु। 2, 96, 1001 बिल रजिस्टर, एनकैशमेंट रजिस्टर और लेखा पुस्तकों में पाए जाते है:

उक्त अपराध के संबंध में, मूल बिल या उक्त बिलों की कार्बन कॉपी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर नहीं की जाती है। राज्य द्वारा दाखिल दस्तावेजों पी–1 और पी–2 के आधार पर, अपचारी सदस्य को उक्त बिलों की राशि की निकासी के लिए अपचारी नहीं ठहराया जा सकता है। केवल बैंक और कोषागार के पत्रों के आधार पर उक्त अपराध को ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता था। संबंधित कार्यालय के किसी भी अभिलेख पर बिलों की प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं हैं। जाँच में, मूल बिल सहायक एजेंसी कोषागार के पास उपलब्ध नहीं हैं और न ही बिलों की कार्बन प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध हैं। उक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्थापित नहीं किया जा सका कि उक्त बिलों को श्री लोकेश कुमार जैन द्वारा वापस ले लिया गया है क्योंकि व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में एक व्यक्ति के लिए पूरे काम को निष्पादित करना संभव नहीं है, अर्थात बिलों का उत्पादन, इसे पारित कराना और उसे वापस लेना। इसलिए श्री लोकेश कुमार जैन के खिलाफ अपराध का दूसरा भाग ठोस और पर्याप्त सबूत के अभाव में साबित नहीं हुआ है।

3. रुपये की राशि का गबन। बजट में साक्षरता और शिक्षा के शीर्ष में अन्य विभाग के बिलों को वापस लेकर 78,179/–। अभियोजन पक्ष ने अपराध के संबंध में (पी–2) (पी–3) का साक्ष्य दाखिल किया है। साक्ष्य के अनुसार, भुगतान उक्त स्पर्श विद्यालय रामा VI धीगरिया के बिलों का भुगतान करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन बजट में सार था। जे साक्षरता और शिक्षा विभाग के प्रमुख के अधीन है।

अपराध का पूरा हिस्सा पूरी तरह से विवादित है। बजट में साक्षरता और शिक्षा शीर्षक में दूसरे विभाग के बिलों को वापस लिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भुगतान किसे प्राप्त हुआ है। केवल व्यय के तथ्य और भुगतान प्राप्त करने के संबंध में कोषागार कार्यालय के आधार पर अपचारी अधिकारी को अपराध का दोषी साबित नहीं होता है। यह संभव है कि अन्य सहायक एजेंसी द्वारा प्रयास किया गया हो। केवल बजट शीर्ष पर विधेयक को पारित करना भी असंभव है। मूल अभिलेखों के पृष्ठों को देखे बिना यह पता नहीं लगाया जा सका कि दोषी अधिकारी ने बैंक से बिलों का भुगतान प्राप्त किया है या नहीं।

निष्कर्षः

कार्यवाही में प्रस्तुत अभिलेखों, साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर और दोनों पक्षों की लिखित और मौखिक दलीलों के आधार पर, हस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराध में कथित विभिन्न बिलों की राशि का भुगतान किसके द्वारा किया गया था, वह संदिग्ध है। उक्त सभी बिल खजांची द्वारा पारित किए गए थे। उक्त पूरे बिलों की मूल और कार्बन प्रतियां विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। केवल सहायक एजेंसियों के पत्रों के आधार पर कथित अधिकारी के खिलाफ अपराध स्थापित नहीं पाया जाता है।

एस. डी. एल.–चितरनाल मीना

जाँच अधिकारी और प्रधान अधिकारी,

आर. ए. यू. विभाग भंडारेज, दौसा

28. पी. एस. राज्य बनाम बिहार राज्य, (1996) 9 एस. सी. सी. 1 में, इस न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ता को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आलोक में विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। आपराधिक मामला लंबे समय से लंबित था, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता को उसी आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था।

29. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि विभागीय कार्यवाहियों में समान आरोप स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, तो कोई आश्चर्य करता है कि आपराधिक कार्यवाहियों में अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए और क्या है जहां अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक विभागीय कार्यवाहियों में अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक से कहीं अधिक है।

30. ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक परिदृश्य और नीचे बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता का वर्तमान मामला उन उपयुक्त मामलों में से एक है जहां उच्च न्यायालय को खंड 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। प्रत्यर्थी द्वारा यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी जो प्राथमिकी में लगाए गए समान आरोपों के संबंध में थी। यह आरोप लगाया गया था कि 15 दिसंबर, 2008 की कैग जांच रिपोर्ट के अनुसार–अपीलकर्ता द्वारा रुपये की हेराफेरी की गई है, मूल बिलों और दस्तावेजों की सभी दं.प्र.सं. के कार्यालय में उपलब्ध हैं और मूल दस्तावेज निदेशालय, राज्य साक्षरता कार्यक्रम के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

31. विभागीय कार्यवाही में ऐसा ही आरोप लगाया गया था कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा रुपये का गबन किया गया था।

32. जाँच एजेंसी (पुलिस) द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद जाँच के दौरान आरोप के संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए। शिक्षा विभाग की फाइल से अपीलार्थी–लोकेश कुमार जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। चूंकि मामला लंबे समय से लंबित था और निकट भविष्य में रिकॉर्ड की उपलब्धता की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ सीजेएम, दौसा के समक्ष एफआर सं.67/2000 दायर किया गया था। सी. जे. एम., दौसा ने अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन पर 18 नवंबर, 2000 के अपने आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 156 (3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया। पी. सी. ने एस. एच. ओ., दौसा को शिकायतकर्ता की सहायता से मामले की फिर से जांच करने और मूल रिकॉर्ड प्राप्त करने का निर्देश दिया। 18 नवंबर, 2000 के आदेश के बावजूद, नौ वर्षों तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जैसा कि 15 दिसंबर, 20 जी 8 की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है।

33. रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, यहां तक कि इस अदालत के समक्ष दायर जवाबी शपथ पत्र के माध्यम से यह दिखाने के लिए कि रिकॉर्ड का पता लगाया गया है ताकि इसे जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सके। जवाबी शपथ पत्र में उल्लिखित मूल दस्तावेजों या साक्ष्य का पता लगाने की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से देरी का आरोप लगाया गया है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि अपीलकर्ता ने जाँच के मामले में देरी की। दूसरी ओर, अन्वेषण अभिकरण के समक्ष मूल अभिलेख या अन्य साक्ष्य की उपलब्धता के संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से मौन रहने से पता चलता है कि प्रत्यर्थी की ओर से निष्क्रियता के कारण देरी हुई। इसलिए, हमारे विचार में, आगे की अवधि के लिए जांच को लंबित रखना व्यर्थ होगा क्योंकि राज्य साक्षरता कार्यक्रम निदेशालय सहित प्रतिवादी को यकीन नहीं है कि क्या जांच के लिए और आरोप घर लाने के लिए मूल रिकॉर्ड प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में देरी प्रत्यर्थी के कारण होती है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित जांच और मुकदमे की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया जाता है और चूंकि अपीलकर्ता को पहले ही विभागीय कार्यवाही में समान

आरोपों के लिए दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को जांच के लिए लंबित रखना अनुचित है, प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए।

34. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन, दौसा में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. (आई. डी. 1) को रद्द प्राथमिकी दिया जाता है।

जी आर. पी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।